

भारत की शैक्षिक प्रणाली और नई शिक्षा नीति 2020

डॉ महेंद्र सिंह झूड़ी

प्रधानाचाय

प्रिंस एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, कन्या कॉलेज,
सीकर, राजस्थान

Email-id -(msinghdudi@gmail.com)

भारत सरकार द्वारा घोषित नई शिक्षा नीति (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020) कोविड-19 महामारी द्वारा प्रस्तुत कठिनाइयों के कारण दुनिया भर में व्याप्त नकारात्मकताओं की भीड़ के बीच एक आमंत्रित परिवर्तन और नई खबर थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कई लोगों द्वारा बिल्कुल अप्रत्याशित थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने जो प्रगति सुझाई है, वह कुछ ऐसी थी जिसे कई शिक्षाविदों ने कभी आते नहीं देखा। हालाँकि शिक्षा नीति ने स्कूल और स्कूली शिक्षा को समान रूप से प्रभावित किया है, यह लेख ज्यादातर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उच्च शिक्षा पर इसके प्रभाव पर केंद्रित है। यह लेख इसी तरह राष्ट्रीय शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण तत्वों का पता लगाता है और जांच करता है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली के लिए उनका क्या महत्व है।

विषय संकेत: प्रभाव, शिक्षा नीति, शैक्षिक प्रणाली

परिचय

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई) भारत के छात्रों और विद्वानों की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा बनाई गई एक नीति है। नीति में ग्रामीण और महानगरीय भारत दोनों में विश्वविद्यालयों के लिए प्राथमिक शिक्षा शामिल है। शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति भारत सरकार द्वारा 1968 में प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी द्वारा, दूसरी प्रधान मंत्री राजीव गांधी द्वारा 1986 में और तीसरी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2020 में घोषित की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020), जिसे 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था, भारत की नई शिक्षा प्रणाली के वृष्टिकोण को दर्शाती है। नई नीति शिक्षा पर पिछली राष्ट्रीय नीति, 1986 की जगह लेती है। नीति प्राथमिक शिक्षा के लिए उच्च शिक्षा के लिए एक व्यापक संरचना है, जैसे कि ग्रामीण और महानगरीय भारत दोनों में पेशेवर तैयारी। नीति 2021 तक भारत की शिक्षा प्रणाली को बदलने की योजना बना रही है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भाषा नीति एक व्यापक नियम और प्रकृति में चेतावनी है; और यह निष्पादन पर समझौता करने के लिए राज्यों, संगठनों और स्कूलों पर निर्भर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति में विभिन्न परिवर्तनों का आदेश देती है। यह जल्द से जल्द अवसर पर राज्य की खपत एक शिक्षा को सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 4% से 6% तक विस्तारित करने का इरादा रखता है। जनवरी 2015 में, पिछले कैबिनेट सचिव टी.एस.आर. सुब्रमण्यम के अधीन न्यासी बोर्ड ने नई शिक्षा नीति के लिए साक्षात्कार चक्र शुरू किया। बोर्ड की रिपोर्ट के आलोक में, जून 2017 में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा 2019 में पिछले भारतीय अंतरिक्ष अन्वेषण संघ (इसरो) के बॉस कृष्णस्वामी कस्तूरीरंगन द्वारा संचालित एक बोर्ड द्वारा प्रस्तुत किया गया था। मसौदा नई शिक्षा नीति (राष्ट्रीय शिक्षा नीति) 2019, बाद में मानव संपत्ति विकास की सेवा द्वारा प्रदान की गई, जिसके बाद विभिन्न सार्वजनिक चर्चाएं हुईं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे में 484 पृष्ठ थे। मसौदा नीति की योजना बनाने में एक गहन साक्षात्कार प्रक्रिया को अपनाया: "2.5 लाख ग्रामपंचायतों, 6,600 वर्गों, 6,000 मेट्रोपॉलिटन नेबरहुड बॉडीज (यूएलबी), 676 लोकेल से दो लाख से अधिक विचार प्राप्त हुए।" राष्ट्रीय शिक्षा नीति का दृष्टिकोण है: "राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक भारत संचालित शिक्षा प्रणाली की कल्पना करती है जो सभी को उत्कृष्ट शिक्षा देकर हमारे देश को उचित और गतिशील सूचना समाज में बदलने में सीधा योगदान देती है।"

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: 21वीं सदी की शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए नई शिक्षा नीति

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की दृष्टि और विज्ञान और नवाचार के अभिनव कार्य के प्रति जिम्मेदारी राष्ट्रीय अन्वेषण प्रतिष्ठान (एनआरएफ) और राष्ट्रीय शैक्षिक नवाचार चर्चा की व्यवस्था के रूप में परिलक्षित होती है। NRF और NETF न केवल महत्वपूर्ण सोच की खोज को पूरा करने और अध्ययन सामग्री की उन्नत संपत्ति बनाने के साथ काम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बल्कि उन आविष्कारशील तरीकों की भी जांच करते हैं जिनके द्वारा नवाचारों का उपयोग छात्रों और विश्लेषकों के लिए किया जा सकता है।

शैक्षणिक संस्थानों के लिए स्वायत्तता

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कुछ दिलचस्प तत्वों में, शायद सबसे अच्छी व्यवस्था शैक्षिक नींवों को अधिक स्वतंत्रता की अनुमति देना है, विशेष रूप से वे जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। यह उन नींवों की भरपाई करने में मदद करेगा जिनका लक्ष्य उत्कृष्टता की ओर है। साथ ही, भारतीय नवाचार संगठनों (आईआईटी) के मॉडल और दिशानिर्देशों पर सौंदर्य विज्ञान / बहु-विषयक शिक्षा और अन्वेषण विश्वविद्यालयों के दस

भारतीय प्रतिष्ठानों की स्थापना के लिए केंद्र सरकार की व्यवस्था भी वास्तव में आवश्यक परिवर्तन प्राप्त करेगी। यह सामाजिक और शैक्षिक क्षेत्रों में बुद्धिमान गतिशील और उन्नति को सशक्त बनाने के साथ-साथ नवीनता और निर्णयिक सोच को बनाए रखने की नीति में सभी प्रकार के विचारों के उच्चारण को दर्शाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा धारा-आधारित शिक्षा प्रणाली से छुटकारा पाने का प्रयास है। इसके बजाय, यह अनुकूलन क्षमता प्रदान करने की प्रतिज्ञा करता है जो छात्रों को रिक्त स्थान / विषयों के एक अलग समूह में उनके उत्साह का पालन करने की अनुमति दे सकता है। एक ओर, यह नीतिगत परिप्रेक्ष्य विद्यार्थियों के लिए अपने निर्णय के विभिन्न विषयों की तलाश करने के लिए कुछ उपयोगी अवसर खोलेगा। यह देखते हुए कि इसे उच्च शिक्षा प्रणाली के साथ स्कूली शिक्षा प्रणाली के समन्वय के तरीके खोजने की आवश्यकता है, इसलिए स्कूली स्तर पर बहु-विषयक विषयों को चुनने वाले छात्रों को पीड़ित या दंडित नहीं किया जाना चाहिए, जब उन्हें अपने निर्णय के विशेषज्ञ अनुशासन में उच्च परीक्षाओं की तलाश करने की आवश्यकता होती है।

भारत में संचालित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय

इसके अलावा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है कि दुनिया के प्रमुख 100 विश्वविद्यालयों में से भारत में काम करने के लिए काम किया जाएगा। यह एक स्वागत योग्य कदम है क्योंकि यह उच्च शिक्षा संगठनों के बीच प्रतिस्पर्धा को उन्नत करेगा और उच्च शिक्षा और अनुसंधान के सामान्य मानदंडों पर काम करेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अतिरिक्त रूप से अनुदान देने, संपत्ति बनाने और सभाओं से छात्रों के लिए कार्यालय बनाने के लिए स्पष्ट रूप से बनाई गई राष्ट्रीय संपत्ति के माध्यम से व्यक्तिगत समझ के लिए मौद्रिक सहायता पर चर्चा करती है। यदि आर्थिक रूप से मजबूर छात्रों की हर एक मौद्रिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक राष्ट्रीय शिक्षा संपत्ति स्थापित की जा सकती है, तो यह 2030 तक सभी स्कूली शिक्षा के लिए 100% सकल नामांकन अनुपात के अपने उद्देश्य को पूरा करने में सरकार की सहायता कर सकती है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नीति रिकॉर्ड के अनुसार 2030-35 तक वर्तमान कुल नामांकन के आधे की सीमा तक अंडरग्रेजुएट स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ाने में मदद कर सकता है। हालांकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कई पथप्रदर्शक व्यवस्थाएं हैं, लेकिन सभी लक्ष्यों को पूरा करना मुश्किल नहीं होगा। कम्प्यूटरीकृत नवोन्मेष की बढ़ती नौकरी के साथ अलग भविष्य की स्थिति में, सबसे बड़ा अंतर शिक्षा की कमी के साथ-साथ शैक्षिक प्रतिष्ठानों के बीच मौजूद अंतर है क्योंकि उनके पास प्रौद्योगिकी के साथ आगे बढ़ने के लिए आवश्यक संपत्ति या ढांचा नहीं है। इसके अलावा, आवश्यक कौशल

और शिक्षा की नींव को बढ़ाने के लिए, प्रशिक्षकों के काम करने की क्षमता और शिक्षकों की तैयारी को भी इस लक्ष्य के साथ गारंटी दी जानी चाहिए कि वे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रभावशाली विशेषज्ञता विकास को संप्रेषित करने के लिए कम्प्यूटरीकृत चरणों और नवाचार उत्तरों का सफलतापूर्वक उपयोग कर सकें।

मौजूदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तुलना:

1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने डेटा नवाचार का उपयोग करते हुए शिक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया। प्रशिक्षक शिक्षा, युवा देखभाल, महिला शिक्षा, और वयस्क दक्षता के पुनर्निर्माण पर अधिक ध्यान दिया गया। पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की निराशा की भरपाई करने के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तरों में बहु-विषयक और क्रॉस-डिसिप्लिनरी शिक्षा और परीक्षा में मदद करने के लिए एक उदार शिक्षा की सिफारिशें हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की नीतियों की मुख्य विशेषताएं

उच्च शिक्षा

1. यूजीसी, एआईसीटीई, एमसीआई, डीसीआई, आईएनसी, आदि जैसे उच्च शिक्षा जांच और नियंत्रण प्रतिष्ठानों को एचईआई के लिए एक अकेले नियंत्रक के रूप में भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (एचईसीआई) के साथ अभिसरण किया जाएगा।
2. नैक जैसे मौजूदा प्रत्यायन प्रतिष्ठानों को एक शक्तिशाली राष्ट्रीय प्रत्यायन चैंबर द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
3. विश्वविद्यालयों और स्कूलों में अनुसंधान का समर्थन करने के लिए एक राष्ट्रीय अन्वेषण प्रतिष्ठान (एनआरएफ) की स्थापना।
4. मौजूदा विभाजित उच्च शिक्षा संस्थानों को दो प्रकार के बहु-विषयक विश्वविद्यालयों और बहु-विषयक स्वतंत्र स्कूलों में 3,000 से अधिक छात्रों के आधार पर समेकित करना।
5. बहु-विषयक विश्वविद्यालय दो प्रकार के होंगे जैसे (1) अन्वेषण केंद्रित विश्वविद्यालय, और (2) उन्नत विश्वविद्यालयों को निर्देश देना।

शिक्षक शिक्षा:

1. सभी स्वतंत्र शिक्षक शिक्षा संगठनों को केवल चार साल के समन्वित बी.एड कार्यक्रम की पेशकश करने के लिए 2030 तक बहु-विषयक उच्च शिक्षा शिक्षण के रूप में खुद को बदलना चाहिए।
2. 2030 तक नई शिक्षा नीति में बीएड कार्यक्रम की समयावधि में बदलाव किया गया है।।
3. एम.एड. अनुसंधान केंद्र के साथ एक वर्ष का होगा। शिक्षा विभागों में कार्मिक प्रोफाइल को विभिन्न क्षेत्रों में पीएचडी के साथ मिश्रित किया जाएगा।
5. सभी इच्छुक वरिष्ठ या इस्तीफा देने वाले कर्मियों को अनुसंधान/तैयारी/उन्नति के लिए निर्देशन, कोचिंग, या विशेषज्ञ सहायता की छोटी या लंबी अवधि के लिए उपयोग किया जाएगा। कोचिंग के लिए एक अलग राष्ट्रीय मिशन स्थापित किया जाएगा।

व्यावसायिक शिक्षा:

1. किसी भी क्षेत्र में सभी स्वतंत्र विशेषज्ञ शिक्षा प्रतिष्ठानों का मतलब 2030 तक समग्र और बहु-विषयक शिक्षा प्रदान करने वाले बहु-विषयक संगठन बनना होगा।
2. उच्च शिक्षा संस्थानों को सामान्य शिक्षा के साथ शामिल कार्यक्रमों के माध्यम से कृषि और पशु चिकित्सा विज्ञान में विशेषज्ञों की योजना बनाने का आग्रह किया जाएगा। कृषि शिक्षा की पेशकश करने वाले उच्च शिक्षा संस्थानों को पड़ोस के स्थानीय क्षेत्र और जिले में कृषि नवाचार पार्क स्थापित करने में सहयोग करना चाहिए ताकि नवाचारों को आगे बढ़ाने और बिखरने को बढ़ावा दिया जा सके।
3. कानून की शिक्षा प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों/फाउंडेशनों को भविष्य के कानूनी परामर्शदाताओं और न्यायाधीशों के लिए अंग्रेजी और राज्य भाषा में द्विभाषी शिक्षा की पेशकश करनी चाहिए।
4. स्वास्थ्य देखभाल शिक्षा प्रणाली को समन्वित किया जाना चाहिए ताकि एलोपैथिक नैदानिक शिक्षा की सभी समझ आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, धूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी के साथ-साथ अन्य तरीकों की एक आवश्यक समझ हो। निवारक चिकित्सा देखभाल और स्थानीय क्षेत्र की दवा के लिए सभी प्रकार की चिकित्सा सेवाओं की शिक्षा में अधिक उल्लेखनीय जोर दिया जाना चाहिए।
5. तकनीकी शिक्षा को बहु-विषयक शिक्षा प्रतिष्ठानों के अंदर प्रस्तुत किया जाना चाहिए और विभिन्न विषयों के साथ गहराई से जुड़ने की स्वतंत्रता पर शून्य होना चाहिए। मानव

निर्मित चेतना (सिम्युलेटेड इंटेलिजेंस), तीन आयामी मशीनिंग, विशाल सूचना जांच, और एआई की पेशकश पर ध्यान दिया जाना चाहिए, भले ही जीनोमिक विचार, जैव प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी, तंत्रिका विज्ञान, भलाई, जलवायु और रखरखाव योग्य जीवन के अनुप्रयोगों के साथ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में नवाचार:

1. 100 शीर्ष भारतीय विश्वविद्यालयों से बाहरी देशों में काम करने का आग्रह किया जाएगा।
2. 100 शीर्ष अपरिचित विश्वविद्यालयों को भारत में काम करने की अनुमति दी जाएगी और उनके साथ काम किया जाएगा।
3. शिक्षा को सभी शर्तों पर आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक अध्ययन कक्ष को प्रौद्योगिकी द्वारा उन्नत किया जाएगा।
4. संकाय व्यक्तियों को एक समर्थित संरचना के अंदर शैक्षिक योजना और शिक्षण पद्धति का अवसर मिलेगा।
5. विद्वता और शोध निष्पादन के आधार पर कार्यबल को प्रेरित करने वाले बल और जिम्मेदारी तय की जाएगी।
6. प्रोग्रामिंग इंटरफेस नीति को संस्थागत विकास योजना में स्पष्ट रूप से चित्रित किया जाएगा।
7. नई नीति व्यावहारिक शिक्षा विकास उद्देश्य को पूरा करने पर केंद्रित होगी।

निष्कर्ष

उच्च शिक्षा प्रत्येक देश में अर्थव्यवस्था, सामाजिक स्थिति, नवाचार का स्वागत, और स्वस्थ मानव आचरण को चुनने में एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निजी क्षेत्र के लिए उच्च शिक्षा को खोलकर और साथ ही प्रत्येक उच्च में गुणवत्ता के साथ बनाए रखने के लिए नियंत्रण के साथ गुणवत्ता, संयम पर काम करने के लिए आविष्कारशील व्यवस्था करके इस तरह के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में चल रही है।

सहभागी संस्थानों के वर्तमान वर्गीकरण के साथ सभी उच्च शिक्षा फाउंडेशन उनके नाम पर डिग्री देने की शक्ति के साथ बहु-अनुशासनात्मक स्वतंत्र स्कूलों के रूप में विस्तारित होंगे या उनके सहायक विश्वविद्यालयों के घटक स्कूल बन जाएंगे। एक निष्पक्ष संगठन नेशनल एक्सप्लोरेशन एस्टाब्लिशमेंट मौलिक विज्ञान, अनुप्रयुक्त विज्ञान, और सामाजिक विज्ञान और मानविकी के आवश्यक अनुसंधान स्थानों में रचनात्मक उद्यमों के लिए वित्त प्रदान करेगा।

विद्यार्थीयों को दिए गए नीति ढांचे के भीतर शैक्षिक योजना, प्रणाली, शिक्षण पद्धति और मूल्यांकन मॉडल चुनने की स्वतंत्रता भी मिलेगी। ये परिवर्तन शैक्षिक वर्ष 2021-22 से शुरू होंगे और वर्ष 2030 तक जारी रहेंगे जहां परिवर्तन का प्रमुख स्तर स्पष्ट है। इसके बाद, भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली प्रशिक्षक से प्रेरित होकर, छात्रों द्वारा संचालित योग्यताओं के लिए प्रेरित अंक, परीक्षण से प्रेरित मूल्यांकन, संचालित खोज के लिए सीखने से प्रेरित, और क्षमता से प्रेरित निर्णय की ओर बढ़ रही है।

संदर्भ

1. ऐथल, पी.एस.; ऐथल, शुभ्रज्योत्सना (2019)। "भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रस्ताव 2019 में उच्च शिक्षा का विश्लेषण और इसके कार्यान्वयन की चुनौतियां"। एप्लाइड इंजीनियरिंग और प्रबंधन पत्र के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल। 3 (2): पीपी. 1-35. एसएसआरएन 3417517
2. नंदिनी, एड. (29 जुलाई 2020), "नई शिक्षा नीति 2020 हाइलाइट्स: बड़े बदलाव देखने के लिए स्कूल और उच्च शिक्षा"। हिंदुस्तान टाइम्स।
3. जेबराज, प्रिसिला (2 अगस्त 2020), "द हिंदू एक्सप्लेन्स | राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्या प्रस्तावित है?"। हिन्दू। आईएसएसएन 0971-751X
4. चोपड़ा, रितिका (2 अगस्त 2020), "नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020"। इंडियन एक्सप्रेस।
5. रोहतगी, अनुभा, एड. (7 अगस्त 2020), "हाइलाइट: राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत में अनुसंधान और शिक्षा के बीच की खाई को कम करने में भूमिका निभाएगी: पीएम मोदी"। हिंदुस्तान टाइम्स।
6. कृष्णा, अतुल (29 जुलाई 2020), "राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हाइलाइट्स: स्कूल और उच्च शिक्षा"। एनडीटीवी।
7. कुमार, के. (2005), 21वीं सदी की शुरुआत में शिक्षा की गुणवत्ता: भारत से सबक। इंडियन एजुकेशनल रिव्यू 40(1), पीपी. 3-28।
8. मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019, <https://innovate.mygov.in/wpcontent/uploads/2019/06/mygov15596510111.pdf>

9. ऐथल, पी.एस. और ऐथल, शुभ्रज्योत्सना (2019), भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रस्ताव 2019 में उच्च शिक्षा का विश्लेषण और इसके कार्यान्वयन की चुनौतियाँ। एप्लाइड इंजीनियरिंग और प्रबंधन पत्र के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल (आईजेएईएमएल), 3 (2), पीपी। 1-35। डीओआई: <http://doi.org/10.5281/Zenodo.3271330>।

10. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020।

11. ओनवुएगबुज़ी, ए.जे., डिकिंसन, डब्ल्यू.बी., लीच, एन.एल., और ज़ोरान, ए.जी. (2009), फोकस समूह अनुसंधान में डेटा एकत्र करने और विश्लेषण करने के लिए एक गुणात्मक ढांचा। गुणात्मक विधियों का अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, 8(3), पीपी। 1-21।

12. ऐथल, पी.एस., (2016), बिजनेस मॉडल, बिजनेस स्ट्रैटेजी, ऑपरेटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड बिजनेस सिस्टम्स, इंटरनेशनल जर्नल इन मैनेजमेंट एंड सोशल साइंस 4(1), पीपी 98-115 के लिए एबीसीडी विश्लेषण तकनीक पर अध्ययन। डीओआई: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1611371>